



जयपुर में लगातार दूसरे दिन भी तेज बारिश हुई। बेमौसमी की यह बारिश किसानों के लिए किसी बड़े सितम से कम नहीं है। सीकर रोड पर स्थित कुकरखेड़ा अनाज मंडी की यह तस्वीर अपने आप यह हाल बयां कर रही है। जो की फसल बेचने मंडी आये किसानों की मेहनत पर अंतिम क्षणों में बारिश ने पानी फेर दिया। मंडी में जगह नहीं मिलने के कारण किसानों को जौ की बोerियां खुले में ही रखनी पड़ीं। अपनी बारी आने और खरीददार मिलने का इंतजार कर रहे किसानों की जौ की बोerियां शुक्रवार को आई तेज बारिश में पूरी तरह से भीग गईं। फसल का सही भाव मिल सके इसके लिए कई किसानों ने सैम्पल के तौर पर काफी सारी जौ खुले में फैला रखी थी, लेकिन ऐन मौके पर आई बारिश ने उनकी महीनों की मेहनत को पूरा चॉपट कर दिया। प्रदेश के किसानों के लिए 15 मार्च के बाद का समय बहुत विकट गुजरता है, पहले ओलों व आंधी ने खड़ी फसलों को खेतों में ही नुकसान पहुंचा दिया और अब लगातार हो रही बारिश ने रही-सही कसर को भी पूरा कर दिया है।

पिकअप-टैकर की टक्कर में भाई-बहन समेत 5 की मौत

जोधपुर, 31 मार्च (कास)। जोधपुर-बीकानेर नेशनल हाईवे पर पिकअप-टैकर की आमने-सामने की टक्कर में भाई-बहन समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 बच्चियां भी घायल हुई हैं। हादसा फलौदी में दोपहर 3 बजे हुआ। पिकअप सवार एक ही परिवार के हैं और घर में आने वाली नई बहू के लिए कपड़े खरीदने गए थे।

पुलिस ने बताया कि बाप में जांबा गांव के लोग कपड़े खरीदने फलौदी गए थे। खरीदारी कर लौटते समय हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप बुढ़ी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और टैकर के आगे के टायर निकल कर बाहर आ गए। हादसे के बाद टैकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

हादसे में पिकअप ड्राइवर पर्वत पुत्र

■ मृतकों में तीन बच्चे हैं तथा दो बालिकाएं गंभीर रूप से घायल हैं।

■ पिकअप में एक ही परिवार के लोग थे और सभी खरीददारी खरीदने गए थे।

जियाराम, उर्मिला (38) पत्नी हरीराम, विकास (20) पुत्र सुभाष, प्रवीण (12) पुत्र ओमप्रकाश और रवीना (12) पुत्री ओमप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई।

घायल अर्पिता (15) पुत्री हरीराम किशोरी और ईसानी (12) पुत्र श्याम लाल को फलौदी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से अर्पिता को जोधपुर रेफर कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार सहरीराम विरसोई के बेटे रमेश का मुकलावा था।

शुक्रवार सुबह परिवार मुकलावा करने के लिए बीकानेर चला गया था। रमेश की चाची उर्मिला ने नई बहू के स्वागत के लिए खरीदारी के लिए कहा। इस पर 4 लोग उर्मिला, ड्राइवर पर्वत और विकास और ईसानी फलौदी गए थे। वापसी में ओमप्रकाश के बेटे-बेटी और भांजे को पिकअप में बैठा लिया। हादसे में तीनों बच्चों की मौत हो गई।

हादसे में मरने वाले रवीना और प्रवीण भाई-बहन हैं। हादसे के बाद घर में कोहराम मच गया।

‘बम ब्लास्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गहलोट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बांटने की राजनीति की है, वर्ष 1984 में सिख भाई-बहनों का नरसंहार कांग्रेस के शासन में हुआ, आतंकवादियों को प्रश्रय व संरक्षण कांग्रेस सरकार के समय दिया गया। शांति प्रिय राजस्थान में साढ़े चार वर्ष से सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों को सरकार संरक्षण मिला हुआ है, कांग्रेस सरकार के खत्म होते जनाधार के कारण मुख्यमंत्री गहलोट कभी टुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, तो कभी खालिस्तान की बात करते हैं।”

सी.पी. जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोट वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में 156 सीट जीतने की बात करते हैं, जबकि गहलोट के दो बार के कार्यकाल में कांग्रेस विधानसभा की 21 और 56 सीटें ही जीत पाई और प्रदेश के आज के हालात देखकर लातना है कि अबकी बार 21 सीट भी नहीं जीत पाएगी। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जनता से कई वादे किए थे, जिनमें किसानों से ऋण माफी, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, संबिदाकार्मियों के नियमितिकरण, कानून व्यवस्था सहित अपराध को रोकने एवं महिला सुरक्षा के वादे शामिल थे, लेकिन राज्य की गहलोट सरकार ने ये वादे पूरे नहीं किए। राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार को वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में जवाब देगी, भाजपा को प्रचंड जनादेश मिलेगा।

नई विदेश व्यापार नीति घोषित, रूपये में ही कारोबार पर पूरा जोर रहेगा

भारतीय निर्यातकों को कोई सामान देश में लाए बगैर उसको तीसरे देश में निर्यात की छूट रहेगी, पूरे देश में डाक निर्यात केन्द्र खोले जायेंगे

नई दिल्ली, 31 मार्च (वार्ता) माल एवं सेवाओं का निर्यात 2030 तक दो लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचाने तथा रूपये में वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों तथा वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं के दौर में नीतिगत निश्चितता, स्थिरता तथा लचीलेपन के रणनीतिक उद्देश्यों के साथ सरकार ने शुक्रवार को ‘आजादी के अमृतकाल’ की पहली ‘विदेश व्यापार नीति’ (एफटीपी) पेश की। परंपरा से हट कर नई एफटीपी-2023 में कोई ‘सनेसट उपबंध’ (पटाक्षेप की तिथि) नहीं रखी गयी है।

विदेश व्यापार नीति के मुख्य बिंदु-

1- नई व्यापार नीति में सनेसट क्लाज (पटाक्षेप) तिथि नहीं है।

■ सरकार ने माल एवं सेवाओं का निर्यात 2030 तक दो लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।

2- वाणिज्य मंत्रालय का भविष्य की उभरती अव्यक्तताओं के अनुसार पुनर्गठन।

3- ई-कामर्स निर्यात को विदेश व्यापार नीति के भी लाभों का पात्र बनाया गया। वेबर-हाउसिंग सुविधा के साथ ई-कामर्स निर्यात केंद्रों को प्रोत्साहन वहां लेबलिंग, प्रोसेसिंग जांच और पैकिंग भी होगी।

4- पूरे देश में ‘डाक निर्यात केंद्र’ खोले जाएंगे।

5- कोई सामान देश में लाए बगैर उसको तीसरे देश में निर्यात की छूट। इसके लिए भारतीय निर्यातकों को रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करने और कुछ अन्य शर्तों के साथ दूसरे देश से खरीदे माल को बाहर ही बाहर तीसरे देश में निर्यात करने की छूट से भारतीय निर्यातकों को गेहूँ जैसी इस समय प्रतिबंधित जिनसे निर्यात का अपना बाजार बनाए रखने की सुविधा होगी।

6- वैश्विक व्यापार में रूपये के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर रूपए को वैश्विक स्तर पर स्वीकार मुद्रा बनाने का लक्ष्य। विदेशी विनियम संकट में फंसे देशों के साथ रूपये में व्यापार को प्रोत्साहन देकर भारत के निर्यात बाजार के संरक्षण और संकटग्रस्त देश की मुश्किल में मदद की पधल।

7- वाराणसी, मिर्जापुर, मुसदाबाद

और फरीदाबाद को निर्यात उत्कृष्टता वाले कस्बों (टीईई) की सूची में जगहा टीईई में साझा सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) को ईपीसीजी योजना का लाभ।

8- बाजारों में प्रवेश की पहल (एमएआई) योजना का विस्तार। 9- राज्यों और जिलों को निर्यात संवर्धन में भागीदार बनाने लिए जिलों को निर्यात का केंद्र बनाने, जागरूकता बढ़ाने राज्य एवं जिला स्तर पर निर्यात संवर्धन समितियां बनाने की नीति। जिला स्तर पर क्षमता विस्तार किया जाएगा।

स्मॉल सेविंग...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अप्रैल से 30 जून तक की तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की नई दरें जारी कर दी गयी है।

कोलंबिया से भारत आयेंगे 60 हिप्पो

नामीबिया से आये चीतों के सफल पुनर्वास से उत्साहित होकर सरकार ने यह फैसला किया है

नई दिल्ली, 31 मार्च। मध्यप्रदेश के कूनों अभ्यारण्य में अफ्रीका से चीतों के आने के बाद अब कोलंबिया से 70 हिप्पो भारत लाए जाएंगे। इन हिप्पो की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि इन्हें दूसरे देशों में भेजा जा रहा है। इसी के तहत एक बड़ी संख्या यानी 70 कोकोन हिप्पो को भारत लाया जाएगा और एक अभ्यारण्य में रखा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 70 ‘कोकोन हिप्पो’ को स्थानांतरित करने की योजना है। इनमें से 60 भारत लाए जाएंगे। दरअसल, ये हिप्पो डूंग स्मगलर पाब्लो एस्कोबार के प्राइवेट चिड़ियाघर में रहे जानवरों के वंशज हैं। इसी कारण से इन्हें कोकोन हिप्पो

कहा जाता है। इन्हें स्थानांतरित करने में 35 लाख डॉलर का खर्च आएगा। यह योजना कोलंबियाई कृषि संस्थान, कोलंबिया वायु सेना और मैक्सिको में ओस्टोक अभ्यारण्य समेत विभिन्न संस्थान के साथ स्थानीय एंटीऑक्विवा सरकार की ओर से किए गए समझौते का हिस्सा है। अभ्यारण्य 10 दरियाई घोंड़ों को ले जाएगा। जबकि शेष 60 को भारत के एक अभ्यारण्य में लाया जाएगा।

पाब्लो एस्कोबार के इलाकों से होते हुए ये जानवर खेत में दूर तक फैल चुके हैं। अधिकारियों की ओर से इनकी आबादी कंट्रोल करने के लिए तरह-तरह के उपाय अपनाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी

संख्या 130 से 160 हो गई है। मूल हिप्पो विदेशी जानवरों के चिड़ियाघर का हिस्सा थे जिसे पाब्लो एस्कोबार ने 1980 के दशक में बनाया था। 1993 में उसकी मौत के बाद ज्यादातर जानवरों को अधिकारियों ने स्थानांतरित कर दिया, लेकिन परिवहन की कठिनाई के कारण उन्होंने हिप्पो को नहीं हटया।

तभी से इन हिप्पो ने तेजी से प्रजनन किया। स्थानीय मैडेलेना नदी के बेसिन के साथ उन्होंने अपना विस्तार किया। देखते ही देखते स्थानीय लोगों और अधिकारियों के लिए एक पर्यावरणीय चुनौती बन गए। 10 हिप्पो मैक्सिको में भेजे जाएंगे।

इस बार फिर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस पर हमला हुआ।

ममता बनर्जी ने सुभेन्दु अधिकारी का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि बंगाल के कई जगहों पर हुई हिंसा में अधिकारी का हाथ है। उन्होंने कहा कि रामनवमी से ठीक पहले अधिकारी ने अमित शाह से मुलाकात की थी। सुभेन्दु अधिकारी सुभमूल के खिलाफ भाजपा के सब से सशक्त नेता हैं। इसी बीच केन्द्रीय गृह मंत्री ने राज्य के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस से बात की और राज्य की कानून व्यवस्था पर जानकार मांगी। राज्यपाल एक-दो दिन में दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया में भी हरेक रामनवमी पर हिंसा होने को लेकर बहस छिड़ी हुई है।

ममता बनर्जी परिचम बंगाल के साथ केन्द्र के भेदभाव को लेकर धरना दे रही हैं। यह ऐसा मुद्दा है जिसे बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टियों आधी सदी से भुना रही है पर अब यह मुद्दा बेअसर हो चुका है।

वाम मोर्चा सरकारों आए दिन इस मुद्दे पर धरना देती थीं और जब भी राज्य सरकार के खराब प्रदर्शन

की बात उठती तब यह मुद्दा जोर शोर से उठाया जाता था।

वर्तमान में ममता बनर्जी की नीतियां व व्यवहार के कारण राज्य में कोई निवेश नहीं आ रहा है। युवा बेरोजगारी व अन्य राज्यों की अपार पलायन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अधिकारियों में सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं क्योंकि युवा काम की तलाश में बाहर चले गए हैं।

राज्य के सरकारी कर्मचारी भी केन्द्र के समान डी.ए. मांग रहे हैं। राज्य में डी.ए. मात्र 4 प्रतिशत है जबकि केन्द्र में 42 प्रतिशत, इससे कर्मचारी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कलाकारों और खिलाड़ियों को मनमाने तरीके से पैसा बांटती हैं। जबकि डी.ए. बढ़ाने के नाम पर पैसा नहीं होने की बात करती हैं।

गुरुवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों ने कलकत्ता में धरना दिया जिन्हें ममता ने “भीकने वाले कुत्ते” करार दिया जिस पर भारी बवाल मचा।

देखा जाना है कि राज्य की वित्तीय स्थिति बेहत दयनीय है बजट घाटा बहुत ज्यादा है ओवर ड्राफ्ट पहले ही सीमा पार कर चुका है।

अमेरिका में ट्रम्प व भारत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शुभर ने एक बयान में कहा कि ट्रम्प के अभियोजन में किसी प्रकार का प्रभावी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उन्होंने ट्रम्प के समर्थकों और आलोचकों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं कानून के अनुसार चलने देना चाहिए। सदन की पूर्व स्वीकार नैसी पेलासी ने ट्वीट कर कहा कि ट्रम्प की अभियोजन में ग्रेण्ड जुरी ने तथ्य एवं विधि सम्मत कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि “कानून से ऊपर कोई नहीं है तथा स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए हर किसी के पास कानूनी सुनवाई का अधिकार है और उम्मीद है कि पूर्व राष्ट्रपति उस सिस्टम का शांतिपूर्ण ढंग से आदर करेंगे, जो उन्हें यह अधिकार प्रदान करता है।”

लुजियाना के हाउस रिपब्लिकन मैजोरिटी लीडर स्टीव स्कलाइज ने भी इस अभियोजन को आमजनजनक बताया। हाउस में सैक्रिफर्ड बैंक के इस रिपब्लिकन ने गुरुवार को ट्वीट किया कि “पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के विरुद्ध न्यूयॉर्क में अभियोजन इसका स्पष्ट उदाहरण है कि चरमपंथी डेमोक्रेट्स अपने राजनीतिक विरोधियों पर प्रहार करने के लिए सरकार को हथियार बना रही है।”

ट्रम्प के सहयोगियों ने यह कहते हुए अभियोजन की भर्त्सना की कि यह पूर्व राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित होने से रोकने का

एक प्रयास है। राष्ट्रपतियों का इतिहास लिखने वाले मैट डलैक ने कहा कि यह अभियोजन अमेरिका में लोकतंत्र का एक संक्रमण काल है और इसमें समान न्याय के सिद्धांत का परीक्षण होगा और हाल ही के इतिहास के वादे शामिल थे, लेकिन राज्य की लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि “यह अभियोजन लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर है और उथल-पुथल को भी परिलक्षित है, जो ट्रम्प ने हमारे सुशासन के सिस्टम के समक्ष प्रस्तुत की है। अतः बातें

भाजपा व कांग्रेस में स्पर्धा है कौन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होड़ मची है। कुमारस्वामी ने कहा कि पर वे स्वयं के बलबूते पर बहुमत लाने और सरकार बनाने के प्रयास में हैं। अगर त्रिशंकु जनादेश मिला और किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, जैसा वर्ष 2018 में हुआ था, उन हालात को देखते हुए कुमारस्वामी का बयान महत्वपूर्ण है। जनता दल (एस) भाजपा व कांग्रेस दोनों के साथ सरकार बना चुकी है। जनवरी 2006 से पार्टी ने भाजपा के साथ सरकार बनाई थी, जो 20 माह चली थी फिर मई 2018 में कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी जो 14 माह चली थी जिसमें कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे।

कुमारा स्वामी ने कहा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लोकल नेता मीडिया के सामने कहा, “मेरी पार्टी को कमतर बताते हैं और बाद में आकर मेरा दरवाजा खटखटाते हैं। सिद्धार्थैया कहते हैं कि जद (एस) का भाजपा से समझौता है वही मुख्यमंत्री बाबुवराज बोम्मई कहते हैं कि जद (एस) का कांग्रेस से समझौता है अगर उन्होंने जद (एस) से सम्पर्क साधने का प्रयास नहीं किया होता तो क्या वे ये सब कहते? वे मेरी पार्टी इस बार खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने कहा 15 साल फंसे रहने के बाद इस बार मैं जनता के सामने आया हूँ जद (एस) का लक्ष्य 224 में से 123 सीटें जीतने और अपने दम पर सरकार बनाने का है।”

इसके पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर हैं। उन्होंने कहा कि “यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वे शायद पहले अथवा पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन पर अभियोग चलाया जाएगा, लेकिन इससे यह एक मूल प्रश्न भी उठता है कि क्या उनकी सुनवाई निष्पक्ष की जाएगी? और क्या वह सुनवाई किसी प्रकार की हिंसा भड़काने के बिना आगे चलेगी? पर अमेरिका के द्विदलीय राजनीतिक सिस्टम के स्थायित्व और यहां कानून के शासन का एक टैस्ट भी होगा।”

हाई कोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को गैर कानूनी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकारी अस्पताल आठ भी कार्यरत हैं।

वहीं महाधिवक्ता, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत से जुड़े थे, ने अदालत को कहा कि कुछ ही डॉक्टर और संस्थाएं इस पूरी हड़ताल को भड़का रहे हैं और यह लोग सरकारी डॉक्टरों को भड़काने में भी कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल डॉक्टरों की पूरी सहमति के बाद ही विधानसभा में पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जिनके निहित स्वार्थ शामिल हैं, वह इन डॉक्टरों को भड़का रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने ही इन अस्पतालों को औंने-पौने दामों पर या मुफ्त जमीन मुहैया कराई है और कई प्राइवेट अस्पताल तो सरकारी स्कीमों की वजह से ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टरों को बिल के किसी प्रावधान से परेशानी है तो वह उसे अदालत में चुनौती दे सकते हैं पर ऐसे हड़ताल करना गैर कानूनी है।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि उन्होंने किसी भी डॉक्टर या डॉक्टरों की संस्था से बातचीत की है कि वह हड़ताल पर क्यों उतरे हैं क्योंकि याचिका में डॉक्टर हड़ताल क्यों कर रहे हैं, इस बारे में नहीं बताया गया है। अदालत ने कहा

कि याचिकाकर्ता ने अखबारों की खबरों को आधार बनाकर याचिका दायर की है। अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि प्राइवेट डॉक्टरों की हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया जाये, बिना उनका पक्ष सुने। इसलिये अदालत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के पैनल वकील अंगद मिर्धा को इस मामले में डॉक्टरों का पक्ष रखने के लिये नोटिस तलब किये हैं और महाधिवक्ता को आदेश दिये हैं कि वह डॉक्टरों और सरकार के बीच हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा अदालत के समक्ष पेश करें।

हैल्थ बिल को स्थागित कर दिया जाये जब तक डॉक्टरों और सरकार के बीच समझौता नहीं हो जाता। यहां उल्लेखनीय है कि राइट टू हेल्थ बिल को विधानसभा में पारित कर दिया गया है परंतु इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इसलिये ये बिल अभी तक क्रियान्वित नहीं हुआ है।

उल्लेखनीय है कि 19 मार्च को, बिल के पारित होने से दो दिन पूर्व, आईएमए की जॉइंट एक्शन कमेटी के पांच सदस्य जिनमें डॉ. सुनील चुध और डॉ. विजय कपूर शामिल थे, ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी अधिकारियों से बातचीत की थी। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने 21 बिन्दुओं

पर सहमति जताई थी और आश्वासन दिया था कि वह इन बिन्दुओं को बिल में जोड़ेगी परंतु जब बिल का अंतिम प्रारूप विधानसभा के समक्ष पेश किया गया तब इनमें से कई बिन्दुओं पर सरकार ने ना तो जोड़ा था बल्कि कई बिन्दुओं पर तो विपरीत कार्य भी किया था।

उदाहरण के तौर पर (1) आइएमए की इस टीम को आश्वासन दिया गया था कि छोटी एवं निजी अस्पतालों पर मुफ्त इलाज का भार नहीं डाला जायेगा और केवल उन्हीं अस्पतालों पर यह भार डाला जायेगा जो इसका आर्थिक भार झेल सकेंगे। (2) दुर्घटना पीड़ितों को रैफरल अस्पताल पहुंचाने के लिये परिवहन सुविधा का भार सरकार को उठाना होगा। (3) दुर्घटना पीड़ितों के लिये मुफ्त इलाज के लिये उचित शुल्क पुनर्भरण व्यवस्था होनी चाहिये। (4) स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल समितियों में ग्राम प्रधान और अन्य स्थानीय प्रतिनिधि नहीं होने चाहिये जो डॉक्टरों के खिलाफ पक्षपात कर सकें। (5) राज्य सरकार के पैकेज में बढ़ावा किया जाये और इन्हें व्यावहारिक बनाया जाये। (6) प्रदेश की 70 फीसदी जनता की सेवा करने वाले निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिये

और इनके सुचारू संचालन के लिये कम लागत की बिजली और पांच वर्ष में फायर एनओसी का नवीनीकरण, पुराने चल रहे अस्पताल भवनों को नियमित करने की सुविधा देनी चाहिये।

सूत्रों का कहना है कि इनमें से किसी भी बिन्दु पर सरकार ने प्रावधान नहीं किये हैं बल्कि विपरीत काम किया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि 19 मार्च को हुई मीटिंग में डॉक्टरों को आश्वासन दिया गया था कि उनकी सारी मांगें स्वीकार की जाएंगी। परंतु उन्हें मीटिंग समाप्त होने के बाद मीटिंग का हस्ताक्षरित ब्यौरा नहीं दिया गया और ना ही मांगों पर अमल किया गया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आईएमए ने राज्यपाल को 25 मार्च यानी बिल के पारित होने के तीन दिन बाद पत्र लिखकर कहा था कि वह राइट टू हेल्थ बिल को विशेष तरह से नियुक्त की गई समिति को भेजें ताकि इस पर पुनर्विचार किया जा सके।

इस पत्र में भी आईएमए ने बिल में कई तरह की कानूनी त्रुटियां गिनाई हैं। परंतु सवाल यह है कि क्या यह पत्र भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा क्योंकि यह भी डॉक्टरों की संस्था द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व है।

स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान

विश्लेषण और आपत्तियां As Given to CM

- महत्वपूर्ण अर्थ वाले सभी संज्ञाओं और शब्दों की उचित परिभाषाएं जो संदर्भित हैं और अर्थ करती हैं, जैसे दुर्घटना, आपात स्थिति, आपातकालीन देखभाल, परिवहन और प्राथमिक उपचार इसमें शामिल होनी चाहिए।
- इस बिल में प्रस्तावित अधिकार केवल राजस्थान राज्य के निवासीयों के लिए होने चाहिए।
- वित्तीय प्रावधानों के बिना निजी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त इलाज की बाध्यता है, निजी अस्पतालों पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं डाला जा सकता है जो पहले से ही संकट में हैं और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसे सार्वजनिक और नामित अस्पतालों के लिए ही निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों और उपलब्ध सुविधाओं के बिना व भुगतान के बिना सभी आपात स्थितियों का इलाज करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए।
- दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त रेफरल परिवहन सुविधा की व्यवस्था सरकार द्वारा ही की जानी चाहिए।
- दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त इलाज के लिए सरकार द्वारा उचित शुल्क पुनर्भरण प्रक्रिया होनी चाहिए।
- जिला स्वास्थ्य समितियों में ग्राम प्रधान और अन्य स्थानीय प्रतिनिधि होंगे, जो डॉक्टरों के खिलाफ पूर्वाह्वी और पक्षपाती हो सकते हैं, जो अंततः स्वास्थ्य सेवाओं को परेशान और बाधित कर सकते हैं। उन्हें प्राधिकरण में शामिल नहीं होना चाहिए।
- डॉक्टरों और अस्पतालों के खिलाफ केवल एक ही शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए, सभी रोगियों को केवल इसका उपयोग करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। राज्य एवं जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण में डॉक्टर ही सदस्य हों, शिकायतों की जांच के लिए केवल विषय विशेषज्ञों को ही निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- सभी प्राधिकरणों में निजी, सरकारी डॉक्टरों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए।
- शिकायत निवारण में प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी को किसी भवन या स्थान में प्रवेश करने, तलाशी लेने और जब्त करने का अधिकार नहीं होने चाहिए।
- द्वेषपूर्ण और झूठी शिकायतों के लिए उचित सजा और दंड के प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए।
- राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण या जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से वर्जित करना असंवैधानिक प्रावधान, इसे हटाना जाना चाहिए।
- मुफ्त दुर्घटना आपातकालीन उपचार और अन्य मुफ्त उपचार केवल सरकारी अस्पतालों और नामित अस्पतालों में ही निर्दिष्ट किए जाने चाहिए।
- रोगियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के अधिकार स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध और अरक्षित होने चाहिए।
- डॉक्टरों को सुरक्षा और उनके खिलाफ हिंसा की रोकथाम प्रदान की जानी चाहिए।
- निजी अस्पतालों पर राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बाध्यता नहीं होनी चाहिए।
- इस अधिनियम के लिए किसी भी प्रकार के नियम बनाने समय हितधारक डॉक्टरों से परामर्श किया जाना चाहिए और मसौदा तैयार करने में उनकी भागीदारी शामिल होनी चाहिए।
- राज्य सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं में तर्कहीन और अनुचित पैकेज दे रहे हैं इसलिए ठीक से गुणवत्तापूर्ण उपचार करना असंभव है, इनके सुधार के लिए प्रावधान और सुझावों के लिए हितधारक डॉक्टरों और अस्पतालों को कमेटी में शामिल और विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- राज्य में मजबूत गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा पर्यटन के लिए निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं को शुरू करने और उचित उपाय करने के लिए सरकार द्वारा प्रावधान होने चाहिए।
- प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी की सेवा करने वाले निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए और इनके सुचारू संचालन के लिए कम लागत की बिजली आपूर्ति, 5 वर्ष में फायर एनओसी का नवीनीकरण, पुराने चल रहे अस्पताल भवनों को नियमित करने जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

19 मार्च को आई.एम.ए. की कमेटी ने डॉ. सुनील चुध के नेतृत्व में सरकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें अधिकारियों ने 21 बिंदुओं पर पूर्ण सहमति जताई थी, परंतु बिल के अंतिम स्वरूप में “हाइलाइटड” बिंदुओं को ना केवल अस्वीकार कर दिया, बल्कि इसके विपरीत कार्य किया गया।